संघे शक्ति सर्वदा सत्यमेव जयते लेखपाल संघ-जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकरण संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओमनगर रोड, आलमबाग बस स्टेशन के सामने, लखनऊ-226005

E-mail: lekhpal.up@gamail.com Website: www.lekhpal.wordpress.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
मो. : +91-9456225600
पत्राचार : मो. शिवदयाल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001 उ.प्र.

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
मो. : +91-9415281875
पत्राचार : कृष्णानगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया उ.प्र.

उपाध्यक्ष
दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
मो.: 9536500281

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
मो.: 9450223683

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
मो.: 9451510484

प्रदेश कोषाध्यक्ष
विनोद कुमार कश्यप
मो.: 9760398504, 9359397188, 8923920103(W)

संगठन मंत्री
सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो.: 9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन)
मो.: 9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
मो.: 9415678593

प्रदेश ऑडिटर
भूपेन्द्र सिंह
मो.: 9198895639

पत्रांक - महामंत्री/239 12-10-2017

सेवा में,

जिलाध्यक्ष/ जिला सचिव,
तहसील अध्यक्ष/सचिव/संयोजक साहबान।
उ0प्र0 लेखपाल संघ।

बन्धुवर,

आपने गतवर्ष एक माह का आन्दोलन बड़े उत्साह व लगन के साथ चलाया था और 30 अगस्त 2016 को विधानसभा के सामने ऐतिहासिक सफल प्रदर्शन किया था जिससे तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उ0प्र0 लेखपाल संघ के साथ सम्मानजनक वार्ता की गयी और समस्त मांगों पर सहमति के साथ ही अधिकारियों को लेखपाल संवर्ग की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने एवं आन्दोलन के कारण की गयी समस्त उत्पीडनात्मक कार्यवाहियां समाप्त करने के निर्देश तत्काल दिए थे। गतवर्ष के आन्दोलन से लेखपाल संवर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई तथा ए0सी0पी0 विसंगति दूर करने की मांग व वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में मा0 परिषद का वर्ष 2008 का जो प्रस्ताव शासन द्वारा पूर्व में खारिज कर दिया गया था, उन्हे आपके सफल आन्दोलन के कारण शासन द्वारा स्वीकार किया गया और मा0 प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा वेतन उच्चीकरण, ए0सी0पी0 विसंगति, पदनाम व शैक्षिक योग्यता परिवर्तन के सम्बन्ध में तर्कपूर्ण व औचित्यपूर्ण प्रबल संस्तुति वेतन आयोग को भेजी गयी तथा वेतन आयोग में सुनवाई के समय भी मा0 प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा प्रबल पैरोकारी की गयी। राजस्व निरीक्षक प्रोन्नति में लेखपाल संवर्ग को वर्ष 2014 में हुई भारी क्षति (पदोन्नति में लेखपाल संवर्ग का कोटा 94 प्रतिशत से घटाकर 55 प्रतिशत किया गया), की भरपायी हेतु राजस्व निरीक्षक के 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती समाप्त कर लेखपाल संवर्ग का पदोन्नति कोटा बढ़ाने का निर्णय लिया गया, और पदोन्नति के अवसर बढ़ाने हेतु प्रत्येक 10 लेखपालों पर एक राजस्व निरीक्षक के अनुपात में राजस्व निरीक्षक के पद करने हेतु 500 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। राजस्व परिषद द्वारा प्रदेश भर में लेखपालों की गलत मौलिक नियुक्तियों को ठीक कराकर वरिष्ठता सूची जारी की गयी जिस पर 3-3 बार आपत्ति का अवसर प्रदान करने के बाद डी पी सी वर्ष 2014-15 से छूटे 254 लेखपालों का प्रमोशन किया गया और वर्ष 2015-16 की नियमित डीपीसी की गयी जिससे 600 लेखपालों को प्रमोशन का लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष 2015-16 की डीपीसी में सेवानिवृत्ति आदि के कारण लेखपाल कोटे के रिक्त रहे 166 पदों का प्रस्ताव पुनः आयोग को भेजा गया है। 27 अक्टूबर 2014 को लेखपालों को लैपटाप दिए जाने की सहमति के बावजूद जो शासन द्वारा लेखपालों को लैपटाप के स्थान पर टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने पर विचार करने लगा था, गतवर्ष के आन्दोलन के कारण 30 नवम्बर 2016 की कैबिनेट में लेखपालों को लैपटाप के साथ-साथ स्मार्टफोन दोनों देने का प्रस्ताव पारित किया गया।

Scanned by CamScanner

बन्धुवर, आपका प्रान्तीय नेतृत्व संवर्ग की 6 सूत्रीय मांगों के शतप्रतिशत पूरा होने तक चैन से बैठने वाला नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री की सहमति/ निर्णय के बावजूद अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के कारण आपके प्रान्तीय नेतृत्व ने नई सरकार के गठन के बाद 11 मई 2017 को मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर संवर्ग की लम्बित मांगों एवं समस्याओं के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शीघ्र समस्त मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। 4 माह प्रतीक्षा के बाद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के कारण दिनांक 27 अगस्त 2017 की बैठक में आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप आन्दोलन का निर्णय लिया गया। जिसकी नोटिस शासन को दे दिया गया है।

बन्धुवर, आपके द्वारा हमारी टीम के पहले 2 वर्षीय कार्यकाल अवधि में लेखपाल संवर्ग की मांगों को लेकर दूसरा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया है। आन्दोलन के प्रथम चरण के पहले दिन 03 अक्टूबर 2017 का आगाज प्रदेश की समस्त तहसीलों शानदार रहा है जिसके लिए आप सभी पदाधिकारी एवं आपके जनपद/ तहसील के समस्त लेखपाल बधाई के पात्र हैं। आपके आन्दोलन के आगाज की आवाज परिषद एवं शासन तक पहुँच गयी है। 03 अक्टूबर को आपके द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन का परिणाम है कि दिनांक 09 अक्टूबर को मा0 राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने आपको वार्ता के लिए बुलाया और उसी दिन सरकार द्वारा राजस्व निरीक्षक के 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती को समाप्त करते हुए समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरने सम्बन्धी राजस्व निरीक्षक नियमावली 2017 कैबिनेट से पारित कर दी। यह सब आपकी शक्ति और संगठन के प्रति समर्पण का प्रतिफल है। इसके बाद लेखपालों के पदोन्नति के अवसर बढकर डेढ़ गुना हो गये हैं। इसके लिए हम मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद, मा0 प्रमुख सचिव राजस्व, मा0 मुख्यसचिव महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं किन्तु अभी सवर्ग की 5 महत्वपूर्ण मांगें शेष हैं उन पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए बिना आन्दोलन समाप्त नहीं किया जा सकता।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 17 अक्टूबर 2017 को समस्त तहसीलों पर 10 बजे से 2 बजे शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ दोगुने उत्साह से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सफल बनाया जाए और 17 अक्टूबर तक समस्त लेखपालों के आय, जाति, निवास के फोल्डर खाली हो जाने चाहिए। इसके बाद ई0 डिस्ट्रिक का कार्य पूरी तरह से बन्द करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए तहसीलों में टेक्निकली एक्सपर्ट लेखपालों को जिम्मेदारी देकर समस्त लेखपालों के पासवर्ड बदलवाकर सुरक्षित करा लिए जाएं। उक्त तिथि को जिला पदाधिकारी जनपद की तहसीलों का भ्रमण कर उत्साहवर्धन करते हुए आन्दोलन को सफल बनाएं। प्रान्तीय पदाधिकारी भी तहसीलों/ जनपदों का भ्रमण कर उत्साहवर्धन करेंगें।

बन्धुवर, आप विश्वास एवं हौसला बनाए रखिए, आपका नेतृत्व 6 सूत्रीय मांगपत्र एवं लेखपाल हितों के प्रति संकल्पबद्ध है। आप सभी आश्वस्त रहें कि आपकी समस्त मांगें पूरी होंगी और आपके नेतृत्व का हर कदम लेखपाल हित में होगा। आप उत्साह और हौसला बनाएं रखिए **"सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती लेकिन दृढ़ संकल्प हो तो एक दिन जरूर मिलती है।"**

दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपका .....

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
महामंत्री

Scanned by CamScanner

ज्ञापन

सेवा में,

मा0 मुख्यमंत्री महोदय,
उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

महोदय, गतवर्ष उ0प्र0लेखपाल संघ द्वारा शासन को छःसूत्रीय मांगपत्र दिया गया था जिसके सम्बन्ध में मा0 राजस्व परिषद द्वारा बैठक में निर्णय लेते हुए प्रस्ताव संस्तुति शासन को भेजे जाने और शासन (राजस्व विभाग) की सहमति के बावजूद कोई शासनादेश/नियमावली निर्गत न होने के कारण लेखपालों को एक माह आन्दोलन करना पड़ा। आन्दोलन के दौरान मा0 महोदय स्वयं आपके द्वारा लेखपाल संवर्ग की मांगों को जायज मानते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय को लेखपाल संवर्ग की सभी 6 जायज मांगों को शीघ्र पूरा करने हेतु पत्र लिखा गया था जिसके बाद दिनांक 21 सितम्बर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उ0प्र0 लेखपाल संघ के साथ की गयी वार्ता में सभी मांगों को औचित्यपूर्ण मानते हुए शीघ्र पूरा करने के निर्देश वार्ता में शामिल अधिकारियों (मा0 मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव राजस्व महोदय) को दिए गये थे। इसके बाद भी निम्न मांगें लम्बित हैं:–

<u>सहमति के बाद लम्बित मॉगे</u>

1. **लेखपाल की शैक्षिक अर्हता स्नातक करने व पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक करने एवं प्रारम्भिक वेतनमान ग्रेड पे 2000 से बढ़ाकर ग्रेड पे 2800 किया जाना।**
2. **ए0सी0पी0 विसंगति दूर करना।**
3. **विशिष्ट परिस्थितियों में लेखपाल को निजी अनुरोध पर प्रदेश के किसी भी जनपद में स्थानान्तण करने सम्बन्धी लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन।**
4. **लैपटाप व स्मार्टफोन उपलब्ध कराना।**
5. **वर्ष 2001 में चयनित , वर्ष 2003–04 में प्रशिक्षित शासन/ परिषद की कमी के कारण 01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त लेखपालों को विज्ञप्ति/चयन/प्रशिक्षण के समय प्रभावी सेवा शर्तो के अनुसार पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ प्रदान करना।**

महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लिए गये निर्णय और दिये गये आश्वासन के बावजूद लेखपाल संवर्ग की कोई मांग पूरी न होने पर उ0प्र0लेखपाल संघ प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 11 मई 2017 को आपसे मिलकर अपनी मांगे पूरी करने का निवेदन किया था जिसपर महोदय द्वारा लेखपाल संवर्ग में प्रोन्नति की खराब स्थिति एवं ए0सी0पी0 विसंगति पर विशेष चिन्ता व्यक्त करते हुए समस्त मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया गया था।

Scanned by CamScanner

महोदय, आपके द्वारा दिये गये आश्वासन के 5 माह व्यतीत होने के पश्चात भी अभी तक लेखपाल संवर्ग की उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है। महोदय, यह स्थिति तब है जबकि लैपटाप के लिए बजट आवंटित है, वेतन उच्चीकरण, ए0सी0पी0 विसंगति, पदनाम व शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन के सम्बन्ध में माननीय राजस्व परिषद व प्रशासनिक विभाग (राजस्व) की तर्कपूर्ण व औचित्यपूर्ण संस्तुति वेतन समिति को अक्टूबर 2016 को संदर्भित है और वेतन समिति द्वारा संगठन व विभाग को सुना जा चुका ।महोदय यह भी कष्ट है कि विगत 5 माह में उ0प्र0 लेखपाल संघ द्वारा आपको और मा0 मुख्यसचिव महोदय को वार्ता/बैठक हेतु कई बार पत्र देने के बावजूद वार्ता/बैठक का समय प्राप्त नहीं हो सका है। जिसके बाद दिनांक 27 अगस्त 2017 को उ0प्र0 लेखपाल संघ की प्रान्तीय बैठक में प्रदेश के 75 जनपदों से शामिल हुए जिलाध्यक्ष/जिलामंत्रियों के द्वारा प्रदेश के 30837 लेखपालों की भावनाओं के अनुरूप आन्दोलन का निर्णय लिया गया जिसकी सूचना महोदय सहित समस्त अधिकारियों को 19 सितम्बर 2017 को दे दी गयी थी।

महोदय, दिनांक 03 अक्टूबर 2017 को प्रदेश की समस्त तहसीलों से उपजिलाधिकारियों के माध्यम से लेखपाल संवर्ग की 6 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में ज्ञापन महोदय की सेवा में प्रेषित किए गये थे। महोदय, दिनांक 09 अक्टूबर 2017 को लेखपाल संवर्ग में प्रोन्नति में स्टेगनेशन की स्थिति को दूर करने हेतु राजस्व निरीक्षक के 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती को समाप्त करने सम्बन्धी राजस्व निरीक्षक नियमावली 2017 को कैबिनेट से पारित कराया गया। जिसके लिए उ0प्र0 लेखपाल संघ महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता है किन्तु महोदय लेखपाल संवर्ग की उपरोक्त महत्वपूर्ण मांगो पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। अतः पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 17 अक्टूबर 2017 से ई0 डिस्ट्रिक (आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य) का कार्य, जो लैपटाप व इण्टरनेट सुविधा के बिना सम्भव नहीं है, बन्द किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त वेतन उच्चीकरण, ए0सी0पी0 विसंगति, पदनाम व शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन, निजी अनुरोध पर विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदेश में स्थानान्तरण सम्बन्धी लेखपाल नियमावली में संशोधन व वर्ष 2001 में चयनित, वर्ष 2003–04 में प्रशिक्षित शासन/ परिषद की कमी के कारण 01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त 1000 लेखपालों को विज्ञप्ति/चयन/प्रशिक्षण के समय प्रभावी सेवा शर्तों के अनुसार पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ प्रदान करने सम्बन्धी मांगों के सम्बन्ध में भी मा0 परिषद के प्रस्ताव एवं मा0 प्रमुख सचिव राजस्व की संस्तुति के अनुसार शीघ्र शासनादेश/ नियमावली निर्गत कराने की कृपा करें।

तहसील अध्यक्ष
तहसील.....
जनपद.....

तहसील सचिव
तहसील.....
जनपद.....

Scanned by CamScanner